एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ

मार्च 2014
खंड XXVIII अंक I

इस अंक में

6 यूके में निवेश क्यों ?
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
8 पिछली तिमाही
9 एक्ज़िम बैंक समाचार
10 भारतीय बागवानी क्षेत्रः व्यापार बढ़ाने के उपाय
11 भारतीय इस्पात उद्योग के लिए सकारात्मक परिदृश्य
12 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएंः वैश्विक वृद्धि की संवाहक
13 एक्ज़िम बैंक गतिविधियां
14 देशों का सूक्ष्मावलोकन
15 मुद्रा प्रवृत्तियां
16 भारतीय इलेक्ट्रोनिक उद्योगः चुनौतीपूर्ण परिदृश्य तथा चीन का महत्व

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

एसएडीसी के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाना

दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) अफ्रीकी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें अंगोला, बोत्सेवाना, डीआर कांगो, लेसोथो, मैडगास्कैर, मलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नाम्बिया, सेशल्सन, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं। अफ्रीका के कुल भू-क्षेत्रफल में इसका 32.5 प्रतिशत और अफ्रीका की कुल जनसंख्या में 27.2 प्रतिशत हिस्सा है। अफ्रीकी क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाकद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। वर्ष 2012 में उप सहारीय अफ्रीका के सांकेतिक जीडीपी में एसएडीसी का 51.1 प्रतिशत और अफ्रीका के जीडीपी में 32.1 प्रतिशत हिस्सा रहा।

दक्षिण अफ्रीका विश्वज में एक अत्यंत खनिज संपन्न क्षेत्र है। यह कई ऊर्जा संसाधनों जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज से संपन्न है। दक्षिण अफ्रीका में हीरे, तेल, यूरेनियम, प्लेटिनम, कोयला और तांबे का विपुल भंडार है। दक्षिण अफ्रीका के पास मैगनीज और प्लेटिनम समूह की धातुओं का भी विश्व में सबसे बड़ा भंडार है और स्वर्ण, हीरे, क्रोमाइट अयस्कश तथा वैनेडियम का प्रचुर भंडार है। अंगोला अफ्रीका में तेल का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व में आठवां सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 11 बिलियन बैरल के अनुमानित तेल भंडार के साथ नामीबिया को अफ्रीका के तेल उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा तेल खिलाड़ी माना जाता है।

2013 में एसएडीसी की जीडीपी वृद्धि दर गत वर्ष में दर्ज की गई 4.2 प्रतिशत की दर पर अपरिवर्तित रही। एसएडीसी देशों का संयुक्त जीडीपी 2012 के 650.2 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 2013 में 637.3 बिलियन यू एस डॉलर रह गया। एसएडीसी देशों का कुल जीडीपी 2014 में 676 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी 2013 में 3,873 यू एस डॉलर अनुमानित था जो 2012 के 3,706 यू एस डॉलर से 4.5 प्रतिशत अधिक है। एसएडीसी के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी 2014 में 4000 यू एस डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है।

एसएडीसी क्षेत्र के भीतर अर्थव्यवस्थाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उदाहरण के लिए, 2012 में, 383.4 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर दक्षिण अफ्रीका का जीडीपी शेष चौदह एसएडीसी देशों के 265.8 बिलियन यू एस डॉलर के संयुक्त जीडीपी से बहुत अधिक था। स्वाजीलैंड को छोड़कर अधिकांश देशों में सामान्य मुद्रास्फीति की बदौलत 2012 में सभी सदस्यै देशों में सकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज हुईं। औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2011 के 8.1 प्रतिशत से घटकर 2012 में 7.5 प्रतिशत हो गयी और 2013 में इसके अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है ।

चार्ट 1 : एसएडीसी का विदेश व्यापार, 2001-2012 (बिलियन यू एस डॉलर)

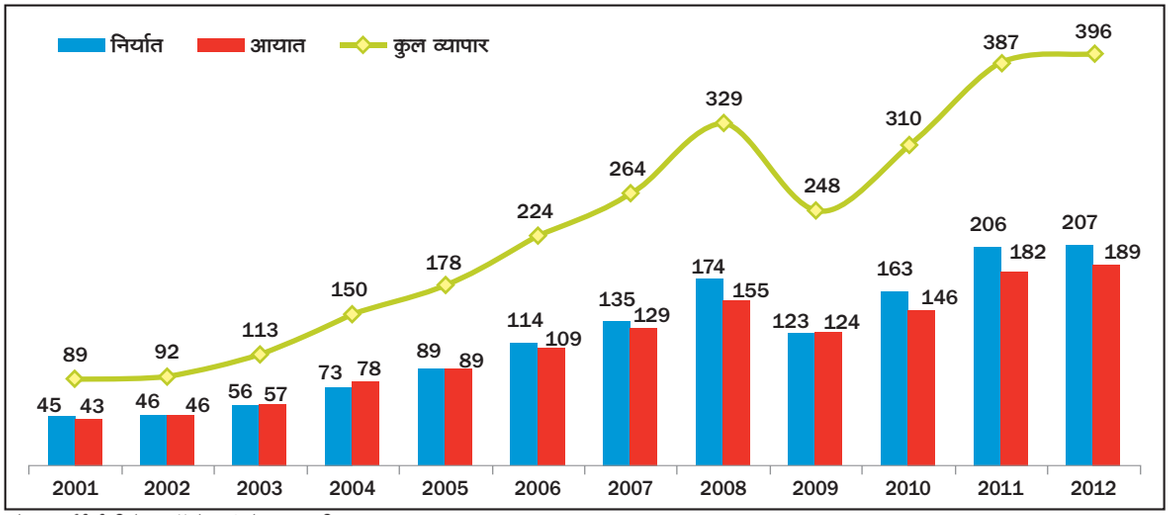

स्रोत : आईटीसी जिनेवा, कॉमट्रेड आंकड़े पर आधारित

एक खंड के रूप में एसएडीसी ने 2011 के 15.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2012 में 30.8 बिलियन यू एस डॉलर का भारी चालू खाता घाटा दर्ज किया। अंगोला, स्वाजीलैंड तथा जाम्बिया को छोड़कर एसएडीसी क्षेत्र के सभी देशों ने वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा दर्ज किया। एसएडीसी का कुल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार 2012 में 111.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो 7 महीने से अधिक के आयात को पूरा करता है।

एसएडीसी का विदेश व्यापार

अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते भूमंडलीकरण को दर्शाते हुए एसएडीसी क्षेत्र के वैश्विक व्यापार में हालिया वर्षों में महत्वपूर्ण उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गयी। 2001 से 2012 के दौरान, एसएडीसी का कुल व्यापार 2001 के 88.7 बिलियन यू एस डॉलर से लगभग पांच गुना बढ़कर 2012 में 395.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जिसमें इस अवधि के दौरान 13.4 प्रतिशत की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गयी। एसएडीसी का कुल निर्यात 2001 के 45.5 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 206.6 बिलियन यू एस डॉलर हो गया, जबकि एसएडीसी के कुल आयात में भी सतत वृद्धि हुई है जो 43.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 188.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया **(चार्ट 1)**।

एसएडीसी के देशों में सबसे बड़े निर्यातक दक्षिण अफ्रीका और अंगोला हैं जिनका 2012 में एसएडीसी के कुल निर्यात में 77.9 प्रतिशत हिस्सा रहा। एसएडीसी से अन्य प्रमुख निर्यातकों में जाम्बिया, बोत्सोवाना, तंजानिया और नामीबिया शामिल हैं। जहां तक आयात का संबंध है, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला क्षेत्र में प्रमुख आयातक हैं जिनका 2012 में एसएडीसी के कुल आयात में 64.7 प्रतिशत हिस्सा रहा।

एसएडीसी से अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हुए खनिज ईंधन एसएडीसी से सबसे बड़ी निर्यात मदें हैं जिनका 2012 में क्षेत्र के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सा रहा। एसएडीसी से निर्यात की अन्य प्रमुख मदों में पर्ल एवं बहुमूल्य रत्न, अयस्का एवं स्लैग, तांबा तथा तांबे की वस्तुएं, वाहन, लोहा एवं इस्पात तथा मशीनरी शामिल हैं। एसएडीसी के निर्यात समूह, जिसमें कच्चें तेल की प्रधानता है, के विपरीत एसएडीसी का निर्यात समूह अपेक्षाकृत विविधीकृत है। खनिज ईंधन एवं मशीनरी दो सबसे बड़ी आयात मदें हैं; इनके बाद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक एवं उसकी वस्तुएं, लोहा एवं इस्पात की वस्तुएं तथा फार्मास्युटिकल उत्पाद शामिल हैं।

हालांकि यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस तथा बेल्जियम जैसे विकसित देश एसएडीसी के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य स्थान बने हुए हैं, चीन तथा भारत जैसे विकासशील देश हाल के वर्षों में प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान के रूप में उभरे हैं। दरसल, 2012 में चीन तथा भारत एसएडीसी के निर्यात के लिए पहले तथा तीसरे सबसे बड़े गंतव्य स्थांन के रूप में उभरे जिनका एसएडीसी के कुल निर्यात में क्रमशः 41.8 प्रतिशत और 8.5 प्रतिशत हिस्सा रहा। एसएडीसी के निर्यात गंतव्य स्थानों की तरह ही, जबकि पश्चिमी देश जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके तथा फ्रांस एसएडीसी के वैश्विक आयात के लिए प्रमुख स्रोत बने रहे जिनका 2012 में एसएडीसी के कुल आयात में 14.1 प्रतिशत हिस्सा रहा। भारत एसएडीसी के आयातके लिए पांचवां सबसे बड़ा स्रोत रहा जिसका हिस्सा 2001 के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 5.1 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2 : एसएडीसी के साथ भारत का व्यापार, 2001-2012 (बिलियन यू एस डॉलर)

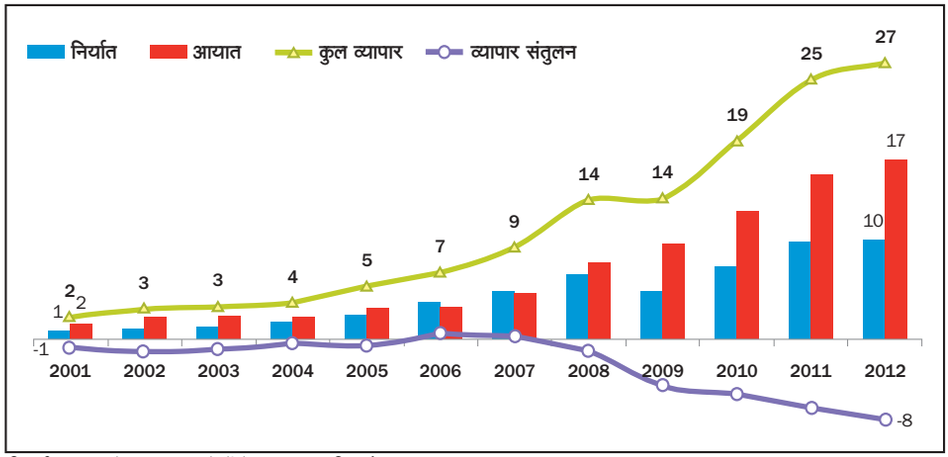

टिप्पणी : 2006 से आयात आंकड़े में तेल आयात शामिल हैं।
स्रोत : आईटीसी जिनेवा, कॉमट्रेड आंकड़े पर आधारित

एसएडीसी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरता भारत

अन्य विकासशील देशों के प्रति भारत के वैश्विक व्यापार के बढ़ते विविधीकरण से एसएडीसी निर्यात बाजार और आयात स्रोत दोनों रूपों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। यह द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सामंजस्य से प्रतिबिम्बित होता है जहां एसएडीसी के साथ भारत का कुल व्यापार (निर्यात-आयात) 2001 के 2.3 बिलियन यू एस डॉलर से लगभग 12 गुना बढ़कर 2012 में 27.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। कुल व्यापार में जोरदार प्रवृत्ति के चलते एसएडीसी के साथ भारत के व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि हुई है **(चार्ट 2)** ।

एसएडीसी को भारत का कुल निर्यात 2001 के 0.7 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 9.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है, जबकि एसएडीसी से भारत का कुल आयात 1.5 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 175 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है। भारत एसएडीसी क्षेत्र के साथ सामान्यतः व्यापार घाटा रखता है जो 2001 के 0.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 7.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

एसएडीसी के व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि 2012 में एसएडीसी के वैश्विक आयात में एसएडीसी को भारत के निर्यात का 2001 के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत का एक सम्मानजनक हिस्सा रहा। इसके अलावा, एसएडीसी से भारत का आयात अब एसएडीसी के कुल निर्यात का लगभग 9 प्रतिशत है जो 2001 में 3.4 प्रतिशत था। यह एसएडीसी के व्यापार विन्यास में भारत के बढ़ते महत्व का द्योतक है।

इस क्षेत्र के महत्व को इस तथ्य से भी आंका जा सकता है कि इस क्षेत्र का 2012 के दौरान अफ्रीका को भारत के कुल निर्यात में 35.3 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि 2001 में यह 26.2 प्रतिशत था। अफ्रीका से भारत के कुल आयात के प्रतिशत हिस्से के रूप में एसएडीसी क्षेत्र से भारत का कुल आयात 2012 में 40.6 प्रतिशत रहा। इसी दौरान भारत के कुल निर्यात में एसएडीसी का हिस्सा 2001 में 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 3.3 प्रतिशत हो गया, जबकि भारत के वैश्विक आयात में क्षेत्र का हिस्सा भी इस अवधि के दौरान 3 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गया।

खनिज ईंधन (मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद) और वाहन एसएडीसी को भारत के निर्यात समूह में सबसे बड़ी मदें हैं जिनका 2012 में एसएडीसी को भारत के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत संयुक्त हिस्सा रहा। एसएडीसी को भारत के निर्यात की अन्य प्रमुख मदों में फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण, अनाज, मशीनरी, प्लास्टिक तथा उसकी निर्मित वस्तुएं तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

जहां तक एसएडीसी से भारत के आयात का संबंध है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम सबसे बड़ी मद है। एसएडीसी से भारत द्वारा अपरिष्कृत पेट्रोलियम का आयात 2006 में 180 मिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 8 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के आयात का भारत के वैश्विक आयात में 5.3 प्रतिशत हिस्सा रहा। अंगोला एसएडीसी से अपरिष्कृत पेट्रोलियम के भारतीय आयात का एकमात्र स्रोत था जिसका अफ्रीका से भारत के कुल आयात में 29 प्रतिशत हिस्सा रहा। अंगोला भारत के अपरिष्कृत पेट्रोलियम के वैश्विक आयात के आठवां सबसे बड़ा स्रोत है और अफ्रीका से दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पर्ल एवं बहुमूल्य रत्नों के अंतर्गत, जो एसएडीसी से भारत के आयात की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है, प्रमुख मदों में मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, बोत्सवाना और स्वाजीलैंड से अपरिष्कृत सोने या अर्ध-निर्मित रूप में सोने तथा अनजड़े हीरे शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका एसएडीसी में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है जिसका 2012 में क्षेत्र को भारत के कुल निर्यात में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा रहा, जो 2001 की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। एसएडीसी में अन्य प्रमुख निर्यात बाजारों में तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस तथा अंगोला शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा आयात स्रोत है। उसके बाद अंगोला, तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक का स्थान है।

एसएडीसी देशों के साथ भारत का व्योपार संतुलन

भारत और एसएडीसी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार (कुल व्यापार) में अंतर्निहित जोरदार प्रवृत्ति एसएडीसी के साथ भारत के व्यापार घाटे की बढ़ती प्रवृत्ति है। एसएडीसी के साथ भारत का व्यापार घाटा 2001 में 0.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 7.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

प्रमुख व्यापार भागीदारों में, जिनके साथ भारत व्यापार घाटा रखता है, सबसे बड़े देश अंगोला तथा दक्षिण अफ्रीका हैं। अंगोला के मामले में, देश से भारी तथा बढ़ती मात्रा में अपरिष्कृत पेट्रोलियम के आयात ने अंगोला के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को रेखांकित किया है। दक्षिण अफ्रीका के मामले में, भारत द्वारा देश से अनजड़े हीरों के आयात के साथ अपरिष्कृत सोने के बढ़ते आयात ने देश के साथ भारी व्यापार घाटे को रेखांकित किया है।

एसएडीसी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाना

हालांकि अधिकांश एसएसीडी देशों के साथ भारत के व्यापार में विगत वर्षों में उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दिखाई दी है, तथापि, इस बात को रेखांकित करना महत्व पूर्ण है कि अधिकांश एसएडीसी देशों के वैश्विक आयात में भारत का हिस्सा मामूली है। उदाहरण के लिए, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया तथा डीआर कांगो के वैश्विक आयात में भारत का हिस्सा मामूली 0.7 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत के बीच है। एसएडीसी क्षेत्र को भारत के निर्यात की संभाव्य मदों, 2 अंकीय एचएस कोड के आधार पर, में शामिल हैंः मशीनरी एवं उपकरण (एचएस-84), इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एचएस-85), रेलवे से इतर वाहन (एचएस-87), ऑप्टिकल, फोटो, तकनीकी तथा चिकित्साए उपकरण (एचएस-90), फर्नीचर, लाइटिंग, साइन्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स (एचएस-94), लोहा एवं इस्पात की वस्तुएं (एचएस-73), नमक, सल्फर, स्टोन, प्लास्टर (एचएस-25), खनिज ईंधन (एचएस-27), पशु, वनस्पति फैट्स एवं तेल (एचएस-15), कार्बनिक रसायन (एचएस-28) तथा पेपर एवं पेपरबोर्ड।

एसएडीसी में एक्ज़िम बैंक

अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ाने की भारत सरकार की रणनीति के अनुरूप और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के वित्तपोषण, संवर्धन और सुगमीकरण लिए भारत में शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में अफ्रीकी देश भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम भारत) के लिए फोकस क्षेत्र बने हुए हैं। एक्ज़िम भारत एसएडीसी में देशों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए वित्तपोषण, सलाहकारी एवं सहायता कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला चलाता है। इनमें वर्तमान में वर्तनशील भारत सरकार द्वारा समर्थित 37 ऋण व्यवस्थाएं, 7 सीधी ऋण व्यवस्थाएं, भारतीय परियोजना निर्यात के लिए सहायता, एसएडीसी देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाली तथा वहां की संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाली कँपनियों को सहायता शामिल है।

एक्ज़िम भारत सीआईआई एक्ज़िम बैंक इंडिया अफ्रीका परियोजना भागीदारी सम्मेलन का एक मुख्य भागीदार है जिसका भारत में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 10 वां सीआईआई - एक्ज़िम बैंक सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में 9 से 11 मार्च 2014 के दौरान आयोजित किया गया। 10 वें सम्मेलन की विषय-वस्तु भारत-अफ्रीकाः नई पहलों के माध्यम से भागीदारी बढ़ाना थी। इस सम्मेलन में लेसोथो भागीदार देश था और कांगो गणराज्य फोकस देश था। इस सम्मेलन में भारत और 40 से अधिक अफ्रीकी देशों दोनों से राज्य प्रमुखों, वरिष्ठ मंत्रियों, राजनयिकों तथा उद्यमियों सहित 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान, भारत सरकार के आदेश पर एक्ज़िम भारत ने कांगो गणराज्य को परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 89.90 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण व्यवस्था प्रदान की। इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक उपकरणों तथा माल के पोतदान / सेवाओं के प्रावधान पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत तक अपफ्रंट प्रतिपूर्ति करेगा।

4 भारतीय अर्थव्यवस्था के संकेतक

संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यू एस डॉलर)	**1224.1**	**1365.4**	**1708.5**	**1880.3**	**1858.7[e]**	**1872.3[f]**
प्रति व्यक्ति जीडीपी (यू एस डॉलर)	**1044.9**	**1146.7**	**1411.7**	**1528.7**	**1486.7[e]**	**1474.0[f]**
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	**6.7**	**8.6**	**8.9**	**6.7**	**4.5[e]**	**4.9[p]**
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	0.1	0.8	8.3	4.4	1.4[e]	4.6[p]
उद्योग	4.4	9.2	7.6	8.5	1.0[e]	0.7[p]
सेवाएं	10.0	10.5	9.7	6.6	7.0[e]	6.9[p]
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सार (%)						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	15.8	14.6	14.5	14.4	13.9[e]	13.9[e]
उद्योग	28.1	28.3	28.2	28.2	27.3[e]	26.2[e]
सेवाएं	56.1	57.1	57.3	57.4	58.8[e]	59.9[e]
जनसंख्या (मिलियन)	**1171.5**	**1190.7**	**1210.2**	**1230.0**	**1250.2[e]**	**1270.6[f]**
मुद्रास्फीति की दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	8.1	3.8	9.6	8.9	7.4	5.7 (मार्च 14)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	**6.0**	**6.5**	**4.8**	**5.8**	**5.2**	**4.6[e]**
विनिमय दर (रु. / यूएस डॉलर, औसत)	45.9	47.4	45.6	47.9	54.4	60.10 (मार्च 28,'14)
विनिमय दर (रु. / यूरो, औसत)	65.1	67.1	60.2	65.9	70.1	82.58 (मार्च 28,'14)
निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)	**185.3**	**178.8**	**251.1**	**306.0**	**300.4**	**312.4**
% परिवर्तन	*13.6*	*-3.5*	*40.5*	*21.8*	*-1.8*	*4.0*
तेल निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)	**27.5**	**28.2**	**41.5**	**56.0**	**60.9**	**56.6 (अप्रैल - फरवरी)**
% परिवर्तन	*-3.0*	*2.3*	*47.2*	*34.9*	*8.7*	*2.1 (अप्रैल - फरवरी)^*
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)	**157.7**	**150.6**	**209.6**	**250.0**	**239.5**	**225.3 (अप्रैल - फरवरी)**
% परिवर्तन	*17.1*	*-4.6*	*39.2*	*19.3*	*-4.2*	*5.0 (अप्रैल - फरवरी)^*
आयात (बिलियन यू एस डॉलर)	**303.7**	**288.4**	**369.8**	**489.3**	**490.7**	**450.9**
% परिवर्तन	*20.7*	*-5.1*	*28.2*	*32.3*	*0.3*	*-8.1*
तेल आयात (बिलियन यू एस डॉलर)	**93.7**	**87.1**	**106.0**	**155.0**	**164.0**	**167.6**
% परिवर्तन	*17.4*	*-7.0*	*21.6*	*46.2*	*5.9*	*2.2*
गैर-तेल आयात (बिलियन यू एस डॉलर)	**210.0**	**201.2**	**263.8**	**334.3**	**326.7**	**283.3**
% परिवर्तन	*22.2*	*-4.2*	*31.1*	*26.7*	*-2.3*	*-13.3*
व्यापार शेष (बिलियन यू एस डॉलर)	**-118.4**	**-109.6**	**-118.7**	**-183.3**	**-190.3**	**-138.6**
सेवा निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)*	**106.0**	**96.0**	**124.6**	**142.3**	**145.7**	**137.9 (अप्रैल - फरवरी)**
*साफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)**	46.3	49.7	53.1	62.2	65.9	50.9 (अप्रैल - दिस.)
सेवा आयात (बिलियन यू एस डॉलर)*	**52.0**	**60.0**	**80.6**	**78.2**	**80.8**	**71.2 (अप्रैल - फरवरी)**
सेवा शेष (बिलियन यू एस डॉलर)*	54.0	36.0	44.0	64.1	64.9	66.7 (अप्रैल - फरवरी)
चालू खाता शेष (बिलियन यू एस डॉलर)#	**-28.7**	**-38.4**	**-47.9**	**-78.2**	**-87.8**	**-31.1 (अप्रैल - दिस.)**
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीएबी	*-2.3*	*-2.8*	*-2.8*	*-4.2*	*-4.8*	*-2.3 (अप्रैल - दिस.)*
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यू एस डॉलर)	**252.0**	**279.1**	**304.8**	**294.4**	**292.6**	**304.2**
विदेशी ऋण (बिलियन यू एस डॉलर)	224.5	260.9	317.9	360.8	404.9	426.0 (दिस.13 के अंत में)
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	20.3	18.2	18.2	20.5	21.8	23.3 (दिस.13 के अंत में)
अल्पावधि ऋण (बिलियन यू एस डॉलर)	43.3	52.3	65.0	78.2	96.7	92.7 (दिस.13 के अंत में)
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	19.2	20.1	20.4	21.7	23.9	21.8 (दिस.13 के अंत में)
कुल ऋण शोधन अनुपात (%)	4.4	5.8	4.3	6.0	5.9	6.2 (जून.13 के अंत में)
एफडीआई (बिलियन यू एस डॉलर)	**41.9**	**37.7**	**34.8**	**46.6**	**34.3**	**31.7 (अप्रैल - फरवरी)**
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यू एस डॉलर)	1.2	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02 (अप्रैल - फरवरी)
एफआईआई निवल (बिलियन यू एस डॉलर)	-15.0	29.0	29.4	16.8	27.6	-0.4 (अप्रैल - फरवरी)
एफडीआई बहिर्वाह (बिलियन यू एस डॉलर)	**19.4**	**15.1**	**16.5**	**10.9**	**7.1**	**6.1 (अप्रैल - फरवरी)**
ज्ञापन मदें:	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014[f]**
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	**-0.4**	**5.2**	**3.9**	**3.2**	**3.0**	**3.6**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	-3.4	3.0	1.7	1.4	1.3	2.2
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	3.1	7.5	6.3	5.0	4.7	4.9
विश्व पण्य व्यापार (परिमाण, % परिवर्तन)	**-11.7**	**14.0**	**6.6**	**2.6**	**2.7**	**4.3**
विश्व पण्य निर्यात (ट्रिलियन यू एस डॉलर)	**12.5**	**15.2**	**18.1**	**18.3**	**18.6**	**19.3**

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक, केन्द्रीय बजट, भारतीय रिज़र्व बैंक की मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं साप्ताहित सांख्यिकीय अनुपूरक, वित्तमंत्रालय, सीएसओ, ईआईयू, नैस्कॉरम, वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ), डब्ल्यूईओ, आईएमएफ ।

टिप्पणी : ईएसी, भारत सरकार के अनुमान, ई-अनुमान, एफ-पूर्वानुमान, % परिवर्तन गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में हैं, उपलब्ध नहीं % 2009-10 से आंकड़े आईएमएफ भुगतान संतुलन मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर भुगतान संतुलन के आंकड़ों के मानक प्रस्तुतीकरण के नये फार्मेट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए हैं।

#अंतरि बजट 2014-15 के अनुसार, भारत का चालू खाता घाटा 2013-14 में 45 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है।

31 मार्च 2014 को अद्यतन किया गया।

चार्ट 1 : 2013-14 में भारत का निर्यात मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

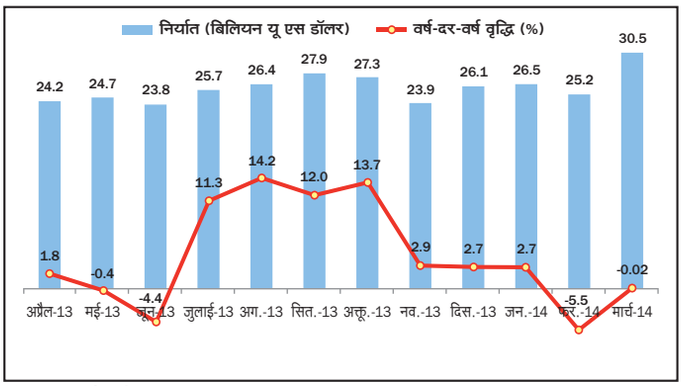

स्रोत : एमओसीआई

चार्ट 2 : 2013-14 में भारत का आयात मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

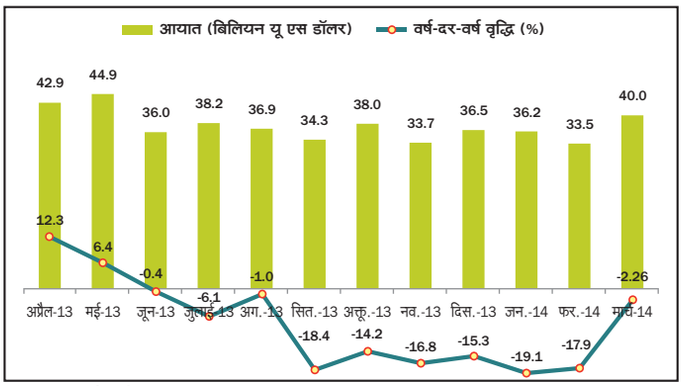

स्रोत : एमओसीआई

चार्ट 3 : 2013-14 में भारत की निर्यात संरचना

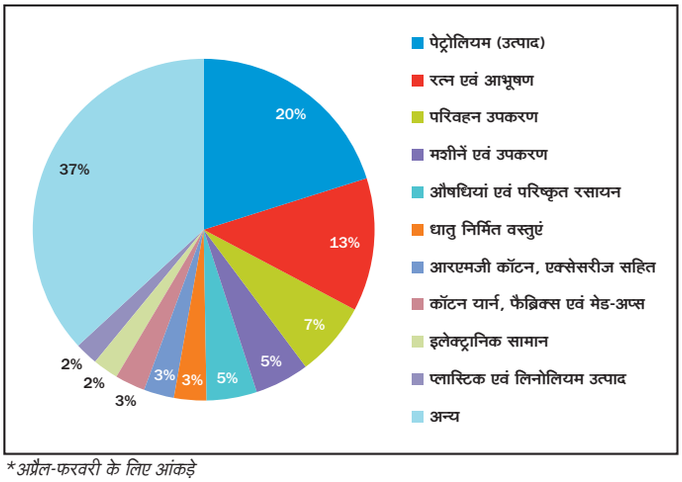

**अप्रैल-फरवरी के लिए आंकड़े*
स्रोत : एमओसीआई

चार्ट 4 : 2013-14 में भारत की आयात संरचना

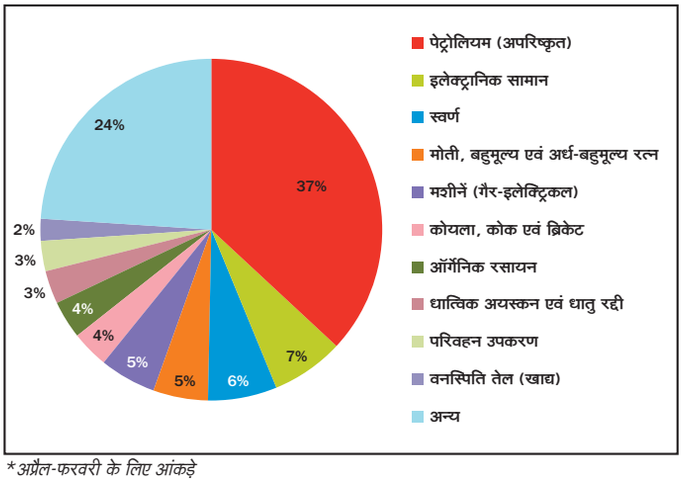

**अप्रैल-फरवरी के लिए आंकड़े*
स्रोत : एमओसीआई

चार्ट 5 : विश्व पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा

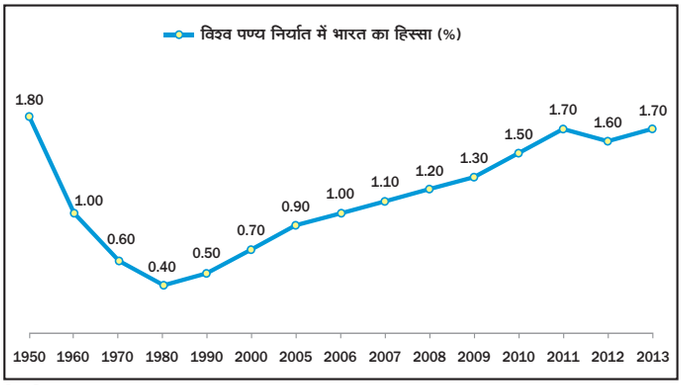

टिप्पणियां :

1. जर्मनी को प्रतिस्थापित करते हुए चीन 2009 में अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरा है।
2. भारत 2013 में 19 वां सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक है जो 2007 के 26 वें स्थान और 2000 के 32 वें स्थान से ऊपर है।

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (31 मार्च 2014 को प्राप्त)

चार्ट 6 : विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा

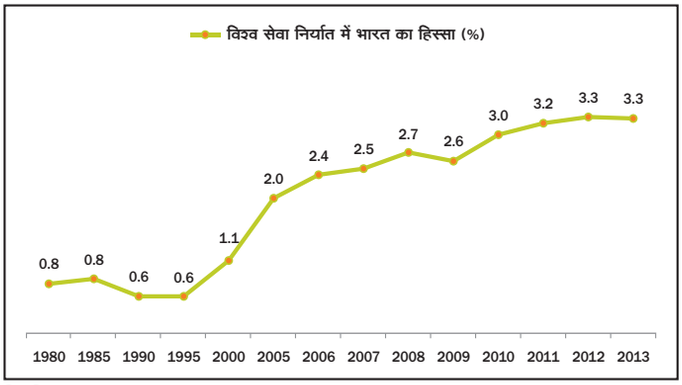

टिप्पणियां :

1. भारत 2013 में छठां सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक है जो 2012 के 7 वें स्थान और 2011 के 9 वें स्थान, 2009 के 11 वें स्थान और 2005 के 15 वें स्थान से ऊपर है।

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (31 मार्च 2014 को प्राप्त)

6 यूके में निवेश क्यों ?

युनाईटेड किंगडम (यूके) विश्व में एक अग्रणी व्यापार केंद्र है। यहाँ जीवन विज्ञान, आईसीटी, रचनात्मक, वित्तीय तथा व्यावसायिक कारोबारी सेवाओं, विमान एवं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जैसे विश्वस्तरीय उद्योग व विकसित बाजार है। यूके ग्राहकों, उत्पाद नवोन्मेषकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा भागीदारों के लिए एक आकर्षक बाजार है।

यूके विश्व के एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। कारोबार एवं आर्थिक अनुसंधान केन्द्र (वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2013) के अनुसार, यूके लगभग 2.4 ट्रिलियन यू एस डॉलर के जीडीपी के साथ विश्व की छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 63.2 मिलियन जनसंख्या के साथ यूके स्वयं में ही एक विशाल बाजार है। यह 28 सदस्य 3 देशों और 500 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं वाले यूरोपीय संघ के लिए प्रवेश-द्वार भी है। यूरोपीय संघ का एक प्रभावशाली सदस्य होने के बावजूद यूके ने अपनी मुद्रा पर संभुता बनाए रखी है। इससे बदलती बाजार स्थितियों में यूके को व्यवसाय परिस्थितियों में लचीलेपन लाने में सहायता मिलती है जो आवक निवेश के लिए काफी फायदेमंद है।

वित्तीय एवं कारोबारी सेवाओं में लंदन एक बेहतरीन केंद्र है जो यूके को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। लंदन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों के जेड/येन ग्रुप के वैश्विक वित्तीय केन्द्र सूचकांक 2013 में पहले स्थान पर रखा गया था।

कोई अंतर्राष्ट्रीय कारोबार प्रारंभ करने वाले वैश्विक उद्यमियों के लिए, यूके एक आदर्श स्थान है जो अत्यंत खुले और गतिशील कारोबारी वातावरण के साथ उद्यमियों के कारोबार को वैश्विक बनाने के लिए एक परिपूर्ण आधार प्रदान करता है। विश्व बैंक के डुइंग बिजनेस 2014 सर्वेक्षण से इस स्थिति की पुष्टि हो जाती है जिसमें कारोबार करने में सुविधा के लिए प्रमुख यूरोपीय देशों में यूके को पहले स्थान पर रखा गया है।

2012-13 के दौरान यूकेटीआई ने 1,559 एफडीआई परियोजनाएं दर्ज कीं जो 2011-12 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। 2012-13 के लिए यूके के आवक निवेश परिणाम तीन वर्षों के लिए जोरदार रहे हैं और यूरोप में एफडीआई के लिए अग्रणी गंतव्य स्थान के रूप में देश की स्थिति की पुष्टि करते हैं। भारत से कारोबारी निवेश का योगदान काफी रहा और यह यूके के लिए वैश्विक रूप से एफडीआई का पांचवां सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और सृजित नये कार्य अवसर की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा है।

देश में 1000 से अधिक कँपनियों द्वारा निवेश किये जाने से यूके को यूरोप में भारत के निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति होता है। भारत यूके के लिए एक मुख्य कारोबारी भागीदार रहा है जो यूके के विज़ा परिचालनों से प्रतिबिम्बित होता है। विश्व भर में यूके का सबसे बड़ा विज़ा परिचालन क्षेत्र भारत है। पिछले वर्ष किए गए कुल कारोबारी विज़ा आवेदनों में से 97 से अधिक आवेदन सफल रहे।

अप्रैल 1996 से मार्च 2014 के दौरान, यूके में ईक्विटी, ऋण तथा जारी गारंटियों संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कँपनियों में संचयी भारतीय एफडीआई (एफडीआई बहिर्वाह) 9.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा। यूके में भारतीय निवेशों में आईसीटी, उन्नत इंजीनियरिंग तथा जीवन विज्ञान में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं। यूके में लगभग 700 भारतीय कँपनियां हैं जिसमें टाटा यूके में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा नियाकू है।

यूके सरकार विदेशी कँपनियों के लिए कारोबारी माहौल काफी अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूके सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की जानकारी के लिए आप भारत में ब्रिटिश उच्चायोग कार्यालयों में यूके व्यापार एवं निवेश स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ukti.gov.uk देखें अथवा uktiindiafco,gov.uk पते पर ई मेल करें ।

यूके व्यापार एवं निवेश (यू के टी आई) एक सरकारी विभाग है जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाए में सफल होने में यूके आधारित कँपनियों की सहायता करता है। यूके की गतिशील अर्थव्यवस्था को वैश्विक कारोबार में सफल होने के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान माना जाता है । यह विदेशी कँपनियों द्वारा यूके में निवेश को भी प्रोत्साहित करता है। यू के टी आई विश्व भर में ब्रिटिश दूतावासों तथा राजनयिक कार्यालयों में विशेषज्ञों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कारोबारियों को सहायता प्रदान करता है।

मुख्य तथ्य

- अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार यूके में 2012 में एफडीआई अंतर्वाह 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 62 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। यह इसके यूरोपीय समकक्षों में सर्वाधिक वृद्धि है।
- विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता 2013-14 रिपोर्ट ने यूके को विश्व में कार्यक्षम श्रम बाजार की दृष्टि से पांचवें स्थान पर रखा है।
- 2015 में कॉर्पोरेशन कर में 20 प्रतिशत की कमी से यह जी-7 देशों में सबसे निम्नतम दर और जी-20 में संयुक्त न्यूनतम दर वाला देश हो जाएगा।
- अर्न्स्ट एंड यंग 2013 के एक सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि यूके ने यूरोप में एफडीआई परियोजनाओं के अग्रणी प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी दीर्घकालीन स्थिति को बनाए रखा है और एफडीआई से उत्पन्नत कार्य अवसरों का अग्रणी प्राप्तकर्ता भी बना हुआ है।
- यूके के पास 100 से अधिक देशों को सम्मिलित करते हुए विश्व में संधियों को सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। कई दशकों से यूके की संधि नीति ब्याज तथा रॉयल्टियों पर विथहोल्डिंग टैक्स को जहां तक संभव हो शून्य तक लाने की रही है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष बल के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एल ओ सी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सौवरिन सरकारी और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकास परक और बुनियादी संरचना, परियोजना, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। साथ ही भारतीय निर्यातक शिपिंग दस्तावेज़ों के एवज में एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान दायित्व रहित आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। एक्ज़िम बैंक स्वयं के अलावा भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यावस्थाएं प्रदान करता है। भारत सरकार के आदेश पर जारी ऋण-व्यवस्थाओं में एक्ज़िम बैंक माल की शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है। बशर्ते कि माल एवं सेवाओं के कुल संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत भारत से लिया जाए। एक्ज़िम बैंक की वर्तमान में 189 ऋण-व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिनके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और सी आई एस के 75 देशों को शामिल करते हुए 10.33 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश और सहयोग से जनवरी-मार्च 2014 तिमाही के दौरान निम्नलिखित छह ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किये हैं:

- मॉरिशस सरकार को विशेषीकृत उपकरणों और वाहनों की खरीद का वित्तपोषण करने के लिए 45 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था। यह भारत सरकार के आदेश पर मॉरिशस सरकार को प्रदान की गई दूसरी ऋण-व्यवस्था है। 48.50 मिलियन यूएस डॉलर की पहली ऋण-व्यवस्थाए अतटीय पेट्रोल वाहनों के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी।

- होंडुरस सरकार को होंडुरस की जैमस्ट्रैन घाटी में कृषि तथा सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 26.50 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था। एक्ज़िम बैंक ने पहले संचार उपकरणों, चिकित्साइ उपकरणों तथा परिवहन उपकरणों के निर्यात के लिए 30 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की थी।

- बुरुंदी सरकार को दो ऋण-व्यवस्थाएं अर्थात बुरुंदी में फार्म यंत्रीकरण के लिए 4.22 मिलियन यूएस डॉलर और बुरुंदी में एक एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण कॉम्लेक्सि के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 0.17 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाएं 4.39 मिलियन यू एस डॉलर की उपर्युक्त दो ऋण-व्यवस्थाओ के साथ एक्ज़िम बैंक ने आज की तारीख तक भारत सरकार के आदेश पर बुरुंदी सरकार को तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं जिससे प्रदान की गई कुल ऋण-व्यवस्थाओं का मूल्य बढ़कर 84.39 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। 80 मिलियन यू एस डॉलर की पहली ऋण-व्यवस्था बुरुंदी में काबु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी।

- कांगो गणराज्य सरकार को कांगो गणराज्य में परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 89.90 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था, यह कांगो सरकार को दूसरी ऋण-व्यवस्था है। एक्ज़िम बैंक ने इसके पहले ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्तपोषण के लिए 70 मिलियन यूएस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की थी। नाइजर सरकार को नाइजर में अर्धशहरी तथा ग्रामीण समुदायों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के वित्तपोषण के लिए 25 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था। यह भारत सरकार के आदेश पर नाइजर सरकार को प्रदान की गई चौथी ऋण-व्यवस्था है। 17 मिलियन यूएस डॉलर की पहली ऋण-व्यवस्था बसों, ट्रको, ट्रैक्टरों, मोटर पम्पों और फ्लोरमिलों के अभिग्रहण के लिए प्रदान की गई थी। 20 मिलियन यूएस डॉलर की दूसरी ऋण-व्यवस्था छह पावर स्टेशनों के पुनर्वास, बिजली ट्रान्सफार्मरों की खरीद और पॉवर लाइनों की स्थापना एवं पुनर्वास के लिए प्रदान की गई थी। 34.54 मिलियन यूएस डॉलर की तीसरी ऋण-व्यवस्था और विद्युतीकरण और सौर फोटो-वोल्टिक प्रणाली की स्थापना के लिए प्रदान की गई थी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

सुश्री गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड,
मुंबई - 400 005.

फोन : (022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

एन ई आई ए के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना निर्यात बढ़ाने पर बैंक का विशेष बल भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसीएन ई आई ए) कार्यक्रम के शुरू होने से बढ़गया है। बीसी एन ई आई ए एक अनोखी वित्तपोषण व्यवस्था है। जो भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प का सुरक्षित साधन प्रदान करता है और विकासशील देशों जिन्हें मध्यावधि या दीर्घावधि आधार पर आस्थगित ऋण की जरूरत होती है में पारम्परिक तथा नये बाजारों में प्रभावी बाजार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक्ज़िम बैंक के माध्याम से परियोजना निर्यात के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता की प्रायोगिक योजना के शुभारंभ की घोषणा की और योजना की कार्य-पद्धति तथा दिशानिर्देश मार्च 2013 में अनुमोदित किये गये।

वर्तमान में ई सी जी सी द्वारा 48 देशों की एक सकारात्मक सूची अनिर्धारित की गई है जिसके लिए भारतीय निर्यातक एन ई आई ए के अंतर्गत क्रेता ऋण प्राप्तव कर सकते हैं।

अन्य देशों से परियोजनाओं के लिए ऋण अनुरोध प्राप्त होने पर सूची को उपयुक्त रूप से बढ़ाया / संशोधित किया जा सकता है। बैंक ने अब तक 520 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की 5 परियोजनाओं के लिए कुल 444 मिलियन यू एस डॉलर की राशि मंजूर की है। बैंक ने कई परियोजनाओं को सहायता देने के लिए सिध्दान्त रूप में वचनबद्धताएं भी दी है और वर्तमान में सक्रिय पाइपलाइन में कई अग्रणी भारतीय परियोजना निर्यातकों के अनुरोध पर बी सी एन ई आई ए के अंतर्गत कुल 7.43 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की 54 परियोजनाएं शामिल हैं।

तीसरी तिमाही में कैड घटकर जी डी पी का 0.9% हुआ

भारत का चालू खाता घाटा (कैड) 2012-13 की तीसरी तिमाही के 31.9 बिलियन यू एस डॉलर (जीडीपी का 6.5 प्रतिशत) से घटाकर 2013-14 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में 4.2 बिलियन यू एस डॉलर (जी डी पी का 0.9 प्रतिशत) रह गया। इसकी मुख्य वजह व्यापार घाटे में गिरावट रही है क्यों कि पण्य निर्यातों में तेजी आयी तथा आयात, विशेषकर स्वर्ण आयात में कमजोरी रही। यह 2013-14 की दूसरी तिमाही से भी कम है, पण्य निर्यात इंजीनियरिंग माल, रेडीमेड वस्त्र, लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद तथा रसायनों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की बदौलत बढ़ा है। परिणामस्वरूप पण्य व्यापार घाटा (भुगतान संतुलन आधार) 2012-13 की तीसरी तिमाही के 58.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2013-14 की तीसरी तिमाही में लगभग 43 प्रतिशत घटकर 33.2 बिलियन यू एस डॉलर रह गया।

भारत का विदेशी कर्ज दिसम्बर 2013 के अंत में जी डी पी का 23.3%

दिसम्बर 2013 के अंत में भारत का कुल विदेशी कर्ज 426.0 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें मार्च 2013 के अंत में दर्ज किए गए 404.9 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत का जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात मार्च 2013 के अंत में 21.8 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर 2013 के अंत में 23.3 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान विदेशी ऋण में वृद्धि दीर्घावधि ऋण, विशेषकर एन आर आई सितम्बर-नवम्बर 2013 के दौरान स्वैप स्कीम के अंतर्गत जुटाई गई नई एफ सी एन आर (बी) जमा राशियों का प्रभाव दर्शाती हैं।

3 डी प्रिंटिंग, अगली औद्योगिक क्रांति

3 डी प्रिंटिंग जैसा कि इसे आज जाना जाता है, उन कई विनिर्माण पद्धतियों में की भांति है जिनका क्रमिक विकास 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित सी एन सी मशीन टूल्स से हुआ था। 3 डी प्रिंटिंग एक विशेष प्रकार की योजक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, जिसमें सामग्री की आनुक्रमिक परतें विभिन्न आकारों में डाली जाती हैं। इसे पारम्परिक मशीनिंग तकनीक से भिन्न माना जाता है जो मुख्यतः कटिंग या ड्रीलिंग जैसी पद्धतियों पर निर्भर थी तथा जिसमें योजक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं होता है। 3 डी प्रिंटिंग के जरिए डिजिटल मॉडल से किसी भी आकार की त्रि-आयामी ठोस वस्तु बनाई जा सकती है।

इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग आभूषण, जूते, औद्योगिक डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग तथा निर्माण (एईसी) मोटर वाहन, विमान, दांत की चिकित्सा उद्योग, शिक्षा, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सिविल इंजीनियरिंग तथा कई अन्य क्षेत्रों में प्ररूपण (प्रोटोटाइपिंग) और विनिर्माण दोनों के लिए किया जाता है।

3 डी प्रिंटिंग के प्रभाव

विनिर्माता फर्मों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाते रहना चाहिए। गुणात्मक विनिर्माण के समर्थकों का यह मानना है कि निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन से भूमंडलीकरण का मुकाबला किया जा सकेगा क्योकि अंतिम प्रयोक्ता अन्य लोगों तथा कार्पोरेशनों से उत्पाद खरीदने के बजाय अपना अधिकांश उत्पांदन स्वयं करेंगे। तथापि, वाणिज्यिक उत्पांदन में नई प्रौद्योगिकियों से पुरानी प्रद्योगिकी को प्रतिस्थापित करने की बजाय उन्हें पारम्परिक पद्धतियों के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

निजी 3 डी प्रिंटिंग

ऐसे लोगों के लिए जो घर पर 3 डी प्रिंटिंग स्वयं शुरू करना चाहते हैं उन के लिए बाजार में कई प्रकार की प्रिंटर किट तथा प्रिंटर उपलब्धत है।

3 डी प्रिंटिंग सेवाएं

कुछ कँपनियां उपभोक्ताओं तथा उद्योगों दोनों के लिए ऑनलाइन 3 डी प्रिंटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं । इसके लिए आपको अपनी 3 डी डिज़ाइन को कँपनी की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है जो औद्योगिक 3डी प्रिंटरों का इस्तेमाल करते हुए आपको 3 डी प्रिंट उपलब्ध करा देती हैं। ग्राहक स्वयं उनके स्टोर से प्रिंट ले सकता है अन्यथा छ कँपनियाँ तो ग्राहकों के घर पर प्रिंट की डिलीवरी सुविधाएँ भी देती हैं ।

नये अनुप्रयोग

3डी प्रिंटरों का इस्तेमाल अब व्यापार अनुकूल प्रॉसथेटिक्स से लेकर स्टाइलिश सितार तक के उत्पाकद तैयार करने में किया जा रहा है। यूके में तो डॉक्टरों ने 3 डी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का अनूठा इस्तेमाल कर एक ऐसे मनुष्य के लिए प्रॉस्थेटिक चेहरा तक तैयार कर लिया जिसके चेहरे के संपूर्ण बाएं हिस्से को कैंसर से ग्रस्त होने के बाद निकलवाना पड़ा था।

नासा भी अपने अंतरर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्द्र में 3 डी प्रिंटिंग का प्रयोग कर रहा है। अपने गहना अंतरिक्ष मिशनों के दौरान विमान के पुर्जे तैयार करने के लिए नासा ने एक उच्च रेज्यूलुशन 3 डी प्रिंटर की मांग की है। यू एस सेना द्वारा भी ट्रक माउंटेड 3 डी प्रिंटरों के जरिए युद्ध क्षेत्र में अतिरिक्त टैंक तथा अन्य पुर्जों का उत्पादन किया जा चुका है। 3 डी प्रिंटिंग के लिए अन्य अनुप्रयोगों में ओपन सोर्स वैज्ञानिक उपकरण निर्मित करना या अन्य विज्ञान आधारित अनुप्रयोग जैसे जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का पुनर्निर्माण, पुरातत्व विज्ञान में प्राचीन तथा अमूल्य शिल्प तथ्यों की प्रतिकृति; फॉरेन्सिक पैथालॉजी में हड्डियों तथा हड्डी के भागों का पुनर्निर्माण और आपराधिक मामलों में अत्यंत क्षतिग्रस्त साक्ष्यो का पुनर्निर्माण शामिल हो सकता है। भवन निर्माण के लिए भी इस प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

श्री यदुवेन्द्र माथुर ने एक्ज़िम बैंक के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया

श्री यदुवेन्द्र माथुर ने एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले श्री माथुर राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी), जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 2011 से कार्यरत थे।

श्री माथुर 1986 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अर्थशास्त्र में सनतक तथा वित्तीय प्रबंधन में एमबीए श्री माथुर 1984 में भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) तथा बाद में 1986 में अपने बैच में टॉप करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए। इससे पूर्व 1982 से 1984 तक वे गोल्डन टोबैको तथा असोसिएटेड सीमेंट्स कम्पनी में मुम्बई में कार्य कर चुके हैं। वे राजस्थान के प्रधान वित्त सचिव सहित वित्त विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। श्री माथुर राजस्थान सरकार में आयोजना सचिव, पी एच ई डी सचिव तथा राजस्व सूचना महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

हाई-टेक निर्यात में वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा : एक्ज़िम बैंक का अध्ययन

विनिर्माण पर केंद्रित सुविधीकृत औद्योगिक आधार सृजित करने के लिए भारत द्वारा रणनीतियां बनाने की दिशा में काफी पहले शुरू किए गए प्रयासों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र की गतिशीलता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में विनिर्माण क्षेत्र का 13.5 प्रतिशत हिस्सा है, जो पिछले एक दशक से स्थिर है। वैश्विक विनिर्माण में आज भारत का हिस्सा मात्र 1.8 प्रतिशत है। भारतीय विनिर्माण का मूल्य योजन रैंक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की तुलना में 52वां है जो कि बांग्लादेश से भी कम है। यह भारत के लिए व्यापार घाटा की स्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बहुत कम हो पाता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की दृष्टि से एक्ज़िम बैंक ने भारत का हाई-टेक निर्यातः संभावित बाजार तथा प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप शीर्षक से भारत से हाई-टेक निर्यात संभाव्यता का विश्लेषण किया है जिसका नई दिल्ली में हाल ही में विमोचन किया गया।

एक्ज़िम बैंक का अध्ययन एसएडीसी क्षेत्र के साथ भारत की व्यापार संभाव्यता पर प्रकाश डालता है

एक्ज़िम बैंक का हालिया प्रकाशन ''दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के साथ भारत की व्यापार संभाव्यताः संक्षिप्त विश्लेषण'' अफ्रीकी प्रांत में एसएडीसी क्षेत्र के बढ़ते महत्व का उजागर करता है। यह क्षेत्र अफ्रीकी महाद्वीप की कुल जी डी पी में 32.1 प्रतिशत का योगदान करता है। दरसल, एसएडीसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था ओंके बढ़ते भूमंडलीकरण को दर्शाते हुए एसएडीसी के वैश्विक व्यापार में हाल के वर्षों मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन में दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के सभी 15 देशों यथा अंगोला, बोत्स्वाना, डी आर कांगो, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, स्वाज़ीलैंड, तंज़ानिया, ज़ाम्बिया तथा ज़िम्बाबे को शामिल किया गया है और अध्ययन 6 श्रेणी तक कुछ ऐसे उत्पादों को रेखांकित करता है जिनमें भारत एसएडीसी को अपना निर्यात बढ़ा सकता है ।

एक्ज़िम बैंक ने भारत-अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एक्ज़िम बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) के साथ 26 मार्च 2014 को जिनेवा में एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईटीसी तथा एक्ज़िम बैंक के बीच इस सहयोग ज्ञापन (एमओयू) से दोनों संस्थाओं के बीच संबंध मजबूत होंगें। सहयोग ज्ञापन उद्यमता विकास व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथसाथ व्यापार सूचना, बाजार विश्लेषण व शोध आदि क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में भी सहायक होगा। इस सहयोग से भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार सहायता नेटवर्कों और व्यवसाय संबंधो को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आईटीसी तथा एक्ज़िम बैंक अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार संबंधों को वरीयता (एसआईटीए) परियोजना को भी सहयोग प्रदान करेंगी जिसकी शुरुआत इस वर्ष में हुई है और जो 2020 तक चलेगी। छह वर्षीय इसपरियोजना का उद्देश्य पांच पूर्व अफ्रीकी देशों इथिओपिया, कीनिया, रवांदा, तंजानिया संयुक्तं गणराज्यी तथा युगांडा से भारत को निर्यात बढ़ाने में मदद करना है। इसके लिए भारत से इन देशों को तकनीकी सहायता और दक्षता प्रदान की जाएगी।

प्रो. किशोर महबुबानी ने एक्ज़िम बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान 2014 दिया

प्रो. किशोर महबुबानी, डीन एवं प्रोफेसर, प्रैक्टिस ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी, ली क्यु आन यू स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर ने 14 फरवरी, 2014 को मुम्बई में एक्ज़िम बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया। उन्होंने 'ग्रेट कनवर्जेंस क्या भारत इसका लाभ उठा पाएगा?' विषय पर अपना व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने निरूपित किया कि किस प्रकार भू-राजनैतिक और आर्थिक दशाओं में आए एक बड़े बदलाव ने 'ग्रेट कनवर्जेंस' जैसी संकल्पना को जन्म दिया है और भारत के लिए नए अवसर खोले हैं।

अपने व्याख्यान में प्रोफेसर महबुबानी ने कहा कि 2020 तक वैश्विक मध्य वर्ग की जनसंख्या 3.2 बिलियन तथा 2030 तक 4.9 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाएगी। अकेले एशिया में ही मध्य वर्ग की जनसंख्या 2010 के 500 मिलियन से तिगुनी होकर 2020 में 1.75 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है जो वैश्विक वृद्धि का 85 प्रतिशत होगी। यह विकास मानव इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है, जिसका पूरे विश्व पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा। हालांकि भारत में यह व्यापक परिवर्तन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। उन्होंने विश्व के बदलते भू-राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत की शक्तियों का विस्तारसे उल्लेख किया।

प्रोफेसर किशोर महबुबानी को सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का भी गहन अनुभव रहा है और साथ ही वे सार्वजनिक मुद्दों पर विस्तारपूर्वक लिखते रहे हैं। उन्होंने सिंगापुर की विदेश सेवा के लिए 33 वर्षों (1971-2004) तक कार्य किया है जहां उनकी पोस्टिंग कम्बोडिया (1973-74), मलेशिया, वाशिंग्टन डी. सी. तथा न्यूयार्क में रही। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दो बार-पहले 2001 में सिंगापुर के राजदूत के रूप में तथा दूसरी बार मई 2002 के दौरान संयुक्त राष्ट्रो सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया है। वे 1993 से 1998 के बीच विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव भी रहे हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. दिलीप एम. नाचणे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

10 भारतीय बागवानी क्षेत्रः व्यापार बढ़ाने के उपाय

कृषि क्षेत्र का वैश्विक कारोबार वर्ष 2012 में 1657 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें भारत के निर्यात का हिस्सा 42.4 बिलियन यू एस डॉलर (विश्व के कुल व्यापार का 2.6 प्रतिशत रहा)। बागवानी क्षेत्र भारत की कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के फल तथा सब्जियों का निर्यात 2.5 बिलियन यू एस डॉलर (विश्व निर्यात का 1.7 प्रतिशत) रहा।

फल तथा सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जबकि सब्जियों की उत्पादकता के मामले में इसका विश्व में दसवां तथा फलों की उत्पादकता के मामले में आठवाँ (11.9 टन प्रति हेक्टर) स्थान है। भारत में जहां फलों की उत्पादकता (19.9 टन प्रति हेक्टर) विश्व स्तर से अधिक है वहीं सब्जियों की उत्पादकता विश्व स्तर से कम है।

भारत से फलों का निर्यात (एच एस कोड 08) 2008-09 के 1410 मिलियन यू एस डॉलर से 6.9 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में 1410 मिलियन यू एस डॉलर हो गया है। जबकि उसी अवधि में सब्जियों (एच एस कोड 07) का निर्यात 776 मिलियन यू एस डॉलर से 7.5 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़कर 1036 मिलियन यू एस डॉलर हो गया है **(तालिका)**। भारत फलों तथा सब्जियों का आयात भी करता है जो कि 2008-09 से 2012-13 की अवधि में क्रमशः 18.4 तथा 14.6 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़ा है। हालांकि भारत से फलों तथा सब्जियों का निर्यात पिछले पाँच सालों में लगातार बढ़ा है तथापि कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में यह अन्य प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में काफी कम (फलों के मामले में 1.1 प्रतिशत सब्जियों के मामले में 1.5 प्रतिशत) रहा है।

निर्यात के वैश्विक रुझानों की तुलना से यह पता चलता है की भारत से निर्यात किए जाने वाले फल व सब्जियों जैसे सेब संतरे, केला, प्याज का निर्यात बाज़ारों में मूली कम मिलता है। इसका एक प्रमुख कारण इनकी अंतरर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तुलना में इनकी गुणवत्ता का कम होना है। इसीलिए हमारे अधिकांश निर्यात एशियाई देशों को ही होते हैं। देश के फलों के निर्यात का 48 प्रतिशत तथा सब्जियों के निर्यात का 70 प्रतिशत एशियाई देशों को होता है। व्यापार विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि हाल के वर्षों मे एशियाई देशों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। फलों पर किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे 72 फलों की श्रेणियों में से उसे केवल 7 में ही प्रतिस्पर्धी बढ़त हासील है। यह सात मदें हैं अंगूर (ताजा व सुखाए गए), अमरूद, आम, मंगुष्ठ, पपीता, खट्टे फल तथा कुछ नट्स हैं। सब्जियों के मामले में (एच एस कोड 07 को एच एस कोड 6 तक विभाजित करने पर) भारत द्वारा निर्यात किए जा रही 69 श्रेणियों में से केवल 9 में ही प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल है। इसके बावजूद फलों तथा सब्जियों दोनों को मिलाकर भारत का वैश्विक निर्यात में 1 प्रतिशत हिस्सा है।

चुनौतियाँ

इस क्षेत्र की चुनौतियां विविध प्रकार की हैं जिसमें आपूर्ति श्रंखला (उत्पादन से लेकर फसल उपरांत प्रबन्धन तक) से लेकर मांग श्रृंखला (गैर प्रशुल्कीय व्यापार अवरोध) तक की चुनौतियाँ शामिल हैं । उत्पादन स्तर पर जहां निम्न उत्पादकता की समस्या है वहीं फसल उपरांत चरण में बरबादी को कम करना है। एक अनुमान के अनुसार भारत में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक फसल बरबादी की दर आम के मामले में 11 प्रतिशत तथा टमाटर के मामले में सबसे ज्यादा है। जिसके चलते बिक्री के लिए माल कम उपलब्ध होता है और व्यापार भी कम होता है। इसके साथ ही निम्नस्तरीय जल प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण पौधे रोपण की कमी, कीटों व रोगों के अकुशल प्रबंधन, तथा छोटे किसानो के लिए उचित प्रौद्योगिकी की कमी आदि भी प्रमुख चुनौतियां हैं। फसल के उपरांत उसके रख-रखाव संबंधी उचित प्रौद्योगिकी का धीमा विकास व प्रसार तथा प्रौद्योगिकी की कमी ऐसे कारण हैं जो इस क्षेत्र में फसल की बरबादी के प्रमुख कारक हैं।

रणनीति

भारतीय बागवानी क्षेत्र में व्यापार, उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत को तीन प्रमुख क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिएः नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाना; फसल का बेहतर प्रबंध कर बरबादी को कम करना तथा; वैश्विक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पाद तैयार करना तथा नए बाजारों में अपनी पैठ बनाना। विभिन्न तरीकों जैसे अच्छी बाजार सूचना पद्धतियों, बेहतर इन्टरनेट व टेलीकॉम सुविधाओं का प्रयोग कर बाज़ार का प्रभावी लाभ उठाना। इसके लिए भारत को घरेलू स्तर पर एक रणनीति तो वैश्विक बाजार के लिए अलग रणनीति बनानी चाहिए।

तालिका - भारत से फलों व सब्जियों का निर्यात

फलों का निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)				सब्जियों का निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)			
देश	2012	हिस्सा (%)	सी ए जी आर (%) 2009 से 2012	देश	2012	हिस्सा (%)	सी ए जी आर (%) 2009 से 2012
विश्व	91.9			विश्व	57.5		
भारत	1.4	1.5	6.9	भारत	1.0	1.5	7.5

Source : Trademap, ITC, Geneva; Exim Bank Analysis

भारत में इस्पात का उत्पादन गत वर्षों मे काफी बढ़ा है जिसने देश को चीन, जापान तथा अमेरिका के बाद क्रूड इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा तथा स्पांज आयरन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया है। क्रूड इस्पात का उत्पादन गत वर्षों मे लगातार बढ़ा है। उत्पादन 2005-06 में जहां 46.6 मैट्रिक टन था वहीं 2012-13 में यह 7.6 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़कर 77.6 मैट्रिक टन हो गया।

वैश्विक स्तर पर आयरन व स्टील का निर्यात घटा है। वर्ष 2008 में जहां निर्यात 827 बिलियन यू एस डॉलर का था वहीं 2012 में यह घटकर 726.2 बिलियन यू एस डॉलर का हो गया। शीर्ष 12 निर्यातकों में से केवल दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान तथा नीदरलैंड को छोडकर बाकी सभी देशों के निर्यात में इस अवधि में गिरावट आई।

पिछले 6 सालों से भारत आयरन व स्टील का निवल आयातक रहा है जिससे व्यापार घाटे में लागातार बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2007-8 में जहां निर्यात 11.8 बिलियन यू एस डॉलर का था वहीं 2012-13 में में यह 5.7 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़कर 15.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। जबकि इसी अवधि में आयात 7.4 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़कर 2007-8 के 12.4 बिलियन यू एस डॉलर से 2012-13 में यह 17.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया **(चार्ट)**। परिणामतः व्यापार घाटा 2007-08 के 0.6 बिलियन यू एस डॉलर से 2012-13 में 2.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

Chart : International Trade in Iron & Steel (US$ bn)

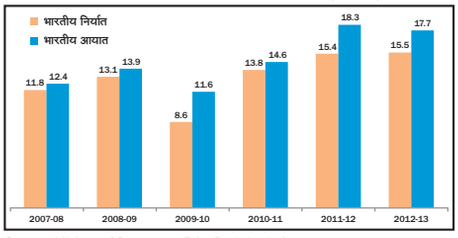

Source : Ministry of Commerce, Exim Bank Analysis

बढ़ता व्यापार घाटा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश के निर्यात में पिछले 6 सालों में आयरन व स्टील का हिस्सा काफी कम हुआ है तथा यह 2006-07 के 7.2 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 5.2 प्रतिशत हो गया।

परिदृश्य

यूरोप तथा विश्व के अन्य हिस्सों आए सुधार से 2014 में वैश्विक स्टील उद्योग में सुधार के संकेत हैं तथा इससे चीन में वृद्धि में मंडी को समंजित करने में मदद मिलेगी। हालांकि अधिक वैश्विक उत्पादन से मूल्यों में उत्साहजनक बढोत्तरी नहीं होगी।

विश्व स्टील संगठन के अनुमानों के अनुसार उपभोग के मामले में चीन में 2006 के बाद से पहली बार उपभोग शेष विश्व के औसत उपभोग से कम रहने का अनुमान है क्योंकि चीन में मांग के 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि शेष विश्व में मांग के 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

भारतीय स्टील उद्योग का निष्पादन तथा परिदृश्य खासकर भारत की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में, पूरी अर्थव्यवस्था में विकास के रुझान तथा शेष विश्व के उसके व्यापार व निवेश तथा तकनीक अन्तरण पर निर्भर करेगा।

अल्पावधि में जहां मांग धीमी रहेगी वहीं दीर्घावधि में मांग बढ़ने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार भारत में स्टील की मांग 2014-15 में बढ़ने का अनुमान है जहां यह प्रमुख अंतिम प्रयोक्ता क्षेत्रों में मांग वृद्धि से संचालित होगी।

मांग बढ़ने तथा कँपनियों द्वारा उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि से 2014-15 में इस क्षेत्र में सशक्त वृद्धि का अनुमान है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से फ्लैट स्टील की मांग बढ़ेगी। जबकि औद्योगिक तथा बुनियादी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के बढ़ने से लॉंग स्टील की मांग बढ़ने का अनुमान है ।

औद्योगिक तथा बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में 2014-15 में मशीनरी की मांग को पूरा करने की आवश्यकता से भी स्टील की मांग बढ़ेगी। सी एम आई ई अनुमानों के अनुसार 2014-15 में स्टील की मांग 2013-14 के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 5.2 प्रतिशत होगी।

चूंकि तैयार स्टील की वृद्धिशील मांग के काफी कम रहने का अनुमान है इसलिए 2014-15 तथा 2015-16 में जब क्षमता वृद्धि संबंधी अधिकांश परियोजनाएं कमीशन की जाएंगी तो मांग-आपूर्ति गैप के बढ़ने की संभावना है। इस बढ़ते मांग-आपूर्ति गैप का लाभ उठाकर निर्माता विदेशी बाज़ारों की ओर रुख कर सकते हैं जहां उन्हें अच्छे मूल्य मिल सकते हैं और वे अपनी परिचालन लागत में कमी को पूरा कर सकते हैं।

रुपये में आई गिरावट, जिसने इसे 62-63 के सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर रखा है, के चलते प्रमुख घरेलू स्टील निर्माता कँपनियों जैसे सेल व जे एस डब्ल्यू द्वारा कोयले की खरीद की लागत बढ़ेगी क्योंकि कोयले के लिए वे मुख्यतः आयात पर निर्भर हैं। विदेशी कर्ज पर ज्यादा निर्भर रहने वाली कँपनियों जैसे टाटा स्टील तथा जे एस डब्ल्यू के विदेशी कर्ज में बढ़ोत्तरी होगी ।

जहां तक कच्चे माल का सवाल है यद्यपि कोकिंग कोल के मूल्यों में कमी आने का अनुमान है किन्तु रुपये के मूल्य में गिरावट से 2013-14 में घरेलू उद्योग को इसका लाभ नहीं मिला पाएगा तथा कोकिंग कोल के मूल्यों में कमी इससे समंजित हो जाएगी। इसके अलावा जहां घरेलू स्तर पर आयरन ओर की आपूर्ति के थोड़ा सुधरने का अनुमान है वहीं कोकिंग कोल की अच्छी कीमत न मिल पाना भारत में स्टील उत्पादकों के लिए चिंता का विषय बनी रहेगी।

घरेलू स्तर पर इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएँ स्टील गहन सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं पर निर्भर केरेंगी जो मुख्यतः शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या के चलते उपभोक्ता वस्तुओं की मांग, बड़े ग्रामीण बाजार तथा घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा क्षमता निर्माण में वृद्धि से संचालित होगी।

12 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएंः वैश्विक वृद्धि की संवाहक

विश्व के लगभग सभी देशों में आर्थिक संकट के बाद आई मंदी से उभरने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे विकास के रास्ते पर आ रही है। वैश्विक क्रिया कलापों में 2013 के दूसरी छमाही के बाद से तेजी आई जिसके 2014 और 2015 में भी बने रहने का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मांग से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बढने का अनुमान है हालांकि कमजोर घरेलू मांग उनके लिए चिंता का विषय बनी रहेगी। वर्ष 2014-15 के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के औसतन 5.3 प्रतिशत की दर से बढने का अनुमान है।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विकासशील एशिया ने विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढत दर्ज करना जारी रखा है। विकासशील एशिया की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2012 के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2013 में 6.5 प्रतिशत रही है। निवेशों में तेजी के चलते क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन 2013 में भी 2012 की 7.7 प्रतिशत की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर हासिल की है। भारत ने भी निर्यातों में वृद्धि तथा आपूर्ति बाधाओं के कम होने के चलते 2012 की 3.2 प्रतिशत की तुलना में 2013 में 4.4 प्रतिशत की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर हासिल की है।

वैश्विक व्यापार के हालिया रुझान

आई एम एफ के हालिया अनुमानों के अनुसार वस्तुओं का वैश्विक निर्यात 18.7 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा जो 2012 के 18.3 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां 2013 में निर्यात की मात्रा में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात की मात्रा में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2014 में वस्तुओं का वैश्विक निर्यात 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 19.6 ट्रिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर रहें का अनुमान है।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मांग के बढ़ने के चलते वैश्विक आयात मांग के भी मध्यावधि में 2012 के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां 2014 में आयात मांग के 2013 के 1 प्रतिशत से बढ़कर 4.1 प्रतिशत रहने तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 2014 में आयात मांग के 2013 के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वैश्विक व्यापार तथा निष्पादन में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का योगदान

वैश्विक व्यापार तथा निष्पादन में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक जी डी पी में इन अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है तथा यह 2001 के 20.5 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 38 प्रतिशत हो गया है जिसके 2014 तक बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं का जहां विश्व के कुल निर्यात में हिस्सा 2002 से 2012 की अवधि के दौरान 66 प्रतिशत से घटकर 51 प्रतिशत हो गया है वहीं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का विश्व के कुल निर्यात में हिस्सा इसी अवधि के दौरान 33 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया ।

विश्व पण्य निर्यातों में पिछले दो दशकों के दौरान तीन गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। जिसमें से एक चौथाई हिस्सा विकासशील देशों का रहा है जिसे दक्षिण-दक्षिण व्यापार भी कहा जाता है और यह 4.7 ट्रिलयन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। दक्षिण-दक्षिण व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान एशिया का रहा है जिसके बाद विकासशील अमेरिका का स्थान रहा है। विकासशील एशिया का कुल अंतर क्षेत्रीय व्यापार 2012 में 3.5 ट्रिलयन यू एस डॉलर के स्तर पर रहा।

ग्राफ : वैश्विक निर्यातों में विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा (%)

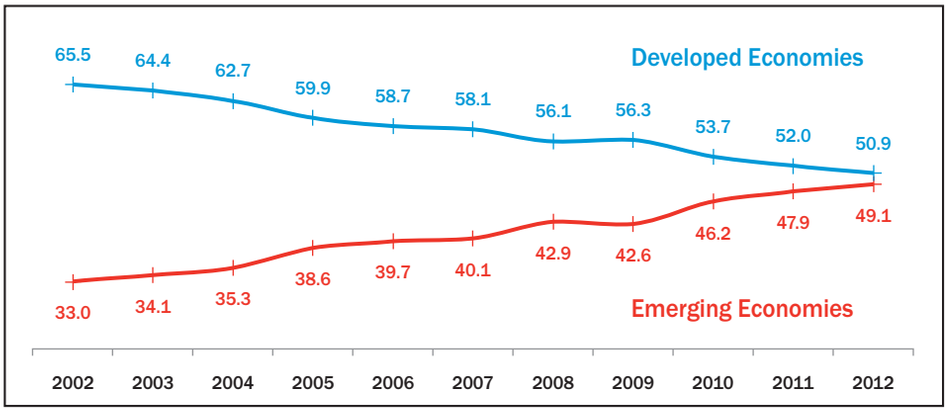

Source : ITC Geneva, based on UN CONTRADE Database

दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाना एशियन एक्ज़िम बैंकस् फोरम 2014

भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में अपनी स्थापना के समय से ही भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार व निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण व संवर्द्धन के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की दिशा में प्रयास करता रहा है। बैंक के इन प्रयासों में एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हमेशा फोकस में रही हैं। एशियन एक्ज़िम बैंकस् फोरम की स्थापना 1996 में भारतीय एक्ज़िम बैंक की पहल पर की गई थी जिसका उद्देश्य फोरम की सदस्य संस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर दीर्घावधि संबंध विकसित करना है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक नवम्बर 2014 में भारत में फोरम की 20 वीं बैठक की मेजबानी करेगा।

ग्रासरूट पहल एवं विकास

बैंक अपनी ग्रामीण ग्रासरूट पहलों के जरिए ग्रामीण भारत में स्थित उद्यमों के ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) में मदद करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पियों, बुनकरों तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसरों व रोजगार का सृजन कर समाज के तुलनात्मक रूप से पिछड़े वर्ग की मदद करना है। इसके लिए बैंक ने चुनिंदा संस्थाओं के साथ संबद्धताएं तथा औपचारिक सहयोग करार किए हैं। इन संस्थाओं के जरिए बैंक इन लोगों तक सीधे पहुँचकर क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार पहुँच, प्रशिक्षण आदि में मदद करता है। इस संदर्भ में वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने ऑस्ट्रिलेज, नीदरलैंड की एक संस्था वुमन ऑन विंग्स के साथ भी एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संस्था विकासशील देशों की महिलाओं की आय को बढ़ाने के लिए काम करती है। संस्था का उद्देश्य भारतीय उद्यमियों को व्यवसाय विकास संबंधी सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर, मानव पूँजी में निवेश को बढ़ावा देकर तथा उनके उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहयोग प्रदान कर वर्ष 2018 तक ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए 1 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने गुजरात स्थित एक ट्रस्ट सहज की मदद की है, जो पूर्व गुजरात के आदिवासी कारीगरों को उनके घरों में ही जीविकोपार्जन हेतु अवसर प्रदान करता है तथा प्रवासन (माइग्रेशन) संबंधी मुद्दों को दूर करने में मदद करता है। बैंक ने इस ट्रस्ट को एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना के लिए मदद की है। बैंक ने कर्नाटक में बेलगाम स्थित एक संस्था मिटान हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट प्रा. लि. को इसकी सी एफ सी के लिए अतिरिक्त रंगाई (ड्राईंग) व बुनाई (विविंग) उपकरणों की खरीद के लिए तथा कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस संस्था में लगभग 700 कारीगर काम करते हैं, जिनमें अधिकांशतः बेलगाम जिले की अर्द्धशुष्क तथा सूखाग्रस्त गाँवों की गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं। बैंक ने ग्रामीण कला एवं शिल्प को बढ़ावा देने वाली एक संस्था अंन्वेषा को आदिवासी महिला कारीगरों द्वारा आभूषण बनाने हेतु एक छोटा वर्कशेड तैयार करने के लिए तथा आवश्यक कार्यशील पूँजी सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआईटी, मद्रास के रूरल टेक्नोईलॉजी बिजनेस इन्क्युबेशन (आर टी बी आई के तत्वावधान में उभरते दो प्रौद्योगिकी उन्मुख संस्थाओं) को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

यह समूह नवोन्मेषी तकनीक आधारित उद्यमों सहित ग्रासरूट उद्यमों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने गोलाघाट, असम में इम्पल्स सोशल एंटरप्राइज प्रा. लि. के साथ मिलकर हैंडलूम कपड़ों को तैयार करने वाली 60 मास्टर महिला कारीगरों के लिए उपयोगिता आधारित कपड़ों की प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए डिज़ाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। बेंगलूरु, कर्नाटक के लखनवल्ली कारीगरों के लिए ग्राम्य टर्नकी सर्विसेस प्रा. लि. के साथ मिलकर प्राकृतिक फाइबर से निर्मित उपयोगी हस्तशिल्प उत्पाद बनाने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 50 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन 'दि आन्ट्स क्राफ्ट ट्रस्ट' के साथ मिलकर किया गया तथा इस कार्यशाला के दौरान लगभग 20 नए उत्पादों के डिज़ाइन तैयार किए गए।

वर्ष के दौरान बैंक ने शीर्ष हथकरघा सोसायटियों तथा निगमों के संघ (ए सी ए एस एच) तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन एच डी सी) के साथ मिलकर भारत हैंडलूम मार्केटिंग कँपनी लि. (बीएचएमसीएल) नामक एक नए संयुक्त उद्यम की स्थापना की। बी एच एम सी एल की स्थापना कँपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कँपनी के रूप में की गई है। यह कँपनी हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करेगी।

विपणन सलाहकारी सेवाएँ
जनवरी-मार्च 2014

बैंक ने अंपने ग्रामीण पहल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों में क्षमता एवं कौशल उन्नयन के लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्रो (एन सी डी पी डी) के साथ मिलकर पोचमपल्ली हैंडलूम प्रा. लिमिटेड के बुनकरों के लिए 10 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बुनकरों तथा टेकनीशियनों के आजीविका में वृद्धि लाने तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु आवश्यक जागरूकता का सृजन, कौशल विकास तथा उनके उत्पादों को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने में सहायता करना है।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने डिज़ाइनरों की मदद से 100 से ज्यादा नए डिज़ाइन तैयार किए। एनसीडीपीडी के डिज़ाइनरों द्वारा लगभग 50 से ज्यादा कारीगरों को कई तरह की डिज़ाइनों का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला से कौशलक्षम बुनकरों को अपनी क्षमता में वृद्धि करने तथा आईकैट उत्पादों की मानक गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा कारीगरों की इन नए-नए डिज़ाइनों व बाजार उत्पादों से बड़े स्तर पर आय के स्रोत बढ़ेगें। प्रतिभागियों द्वारा घरों में प्रयोग की जाने वाली कई तरह की वस्तुओं को तैयार किया गया जिनमें पर्दे, मेजपोश (टेबल कवर), कुशन कवर, तकिया, उपयोग में लायी जाने वाली बॉक्स, टिशू पेपर बॉक्स , फोटो फ्रेम, लेडिज बैग तथा पैकिंग बॉक्स आदि तैयार किए गए। उपयोग में न लायी जाने वाली वस्तुओं से कुछ नए उत्पाद जैसे बेल्ट, नेकलेक्स आदि भी तैयार किए गए। इसका उद्देश्य कई तरह के कपड़ों तथा मोतियों आदि को मिलाकर उत्पाद लागत को कम करना तथा कुछ नए आकर्षक उत्पादों को तैयार करना है।

बैंक अपने विपणन सलाहकारी कार्यक्रम के जरिए भारतीय कँपनियों में क्षमता निर्माण तथा उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अंदा करता है। बैंक भारतीय निर्यातकों के उत्पादों एवं सेवाओं हेतु विदेशी वितरकों/ क्रेताओं/सहभागियों की तलाश करने में मदद करता है। विपणन सलाहकारी कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक अंपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अच्छी जानकारी, अपनी उपस्थिति तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर सफलता शुल्क आधार पर भारतीय कँपनियों की उनके विदेशी विपणन प्रयासों में मदद करता है।

Ethiopia

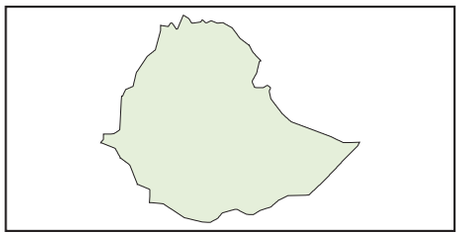

Ethiopia is one of the fastest growing non-oil economies in Africa. The country plans to attain middle-income status by 2020. While Ethiopia has reportedly witnessed tangible progress on the UN's Millennium Development Goals (MDGs), the International Monetary Fund (IMF) has noted that there still remains a pressing need for policies to translate positive growth outcomes into stronger employment gains and further reduction in poverty and set off a dynamic, virtuous cycle of self sustaining and broad-based growth. The country has attracted significant foreign investment in textiles, leather, commercial agriculture and manufacturing. In February 2014, the World Bank approved funds to help Ethiopia upgrade its road system, strengthen road maintenance and reduce travel time along inter-regional corridors. The project is aligned with the Growth and Transformation Plan and supports economic expansion.

Bangladesh

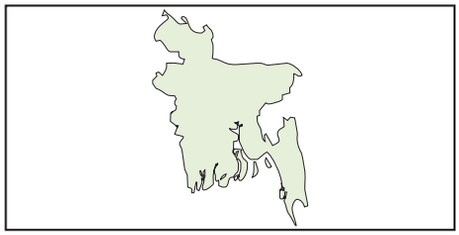

In its most recent review of the Bangladeshi economy (December 2013), the IMF praised the country's macroeconomic policies and approved the disbursal of US$ 140 million under its Extended Credit Facility Arrangement, but cautioned that political risk and the frequency of strikes and industrial disasters will reduce growth in coming years and could risk the progress that Bangladesh has made towards reducing poverty. Dun and Bradstreet recently downgraded Bangladesh due to ongoing civil unrest. Bangladesh held general elections in 2014 but the process was marred by voting irregularities and government restrictions on the opposition's right to campaign. Local companies have reported large declines in export orders in the second half of 2013. Services and industrial activity has also fallen in the latter part of the year, according to the central bank.

Vietnam

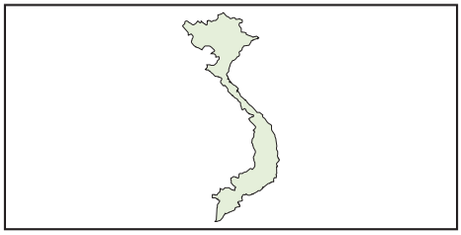

Vietnam joined the World Trade Organisation in January 2007, which has promoted more competitive, export-driven industries. Vietnam also became an official negotiating partner in the Trans-Pacific Partnership trade agreement in 2010. Agriculture's share in GDP has continued to shrink from about 25 per cent in 2000 to less than 20 per cent in 2012, while the share of industry has increased from 36 per cent to more than 42 per cent in the same period. State-owned enterprises account for about 40 per cent of GDP. Between 2008 and 2011, Vietnam's managed currency, the dong, was devalued in excess of 20 per cent, but its value remained relatively stable in 2013. In February 2011, the central bank shifted from policies aimed at achieving a high rate of economic growth, which had stoked inflation, to those aimed at stabilising the economy, through tighter monetary and fiscal control. The government has committed to restructuring the banking sector, with partial privatisation of major state-owned banks.

Rwanda

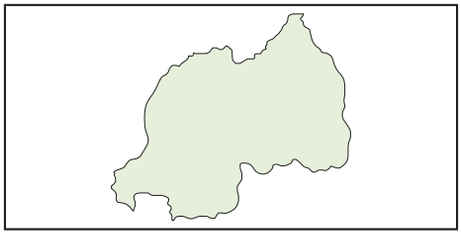

The 2014 World Bank Doing Business Report has ranked Rwanda 52nd out of 189 countries, and the second best country in Africa to do business, after Mauritius, and before South Africa and Botswana. The country has adopted policies and institutional arrangements considered “best practice” by the World Bank's “Doing Business” surveys, resulting in increasing investor interest for investments. Data from Mining in Africa Country Investment Guide 2014 reveals that the country has untapped wealth and steady rise in mineral revenues. The IMF predicts the economy to grow by 7.5 per cent in 2014 but warns that the financial system is too weak to offer the government the possibility of getting more financing from the domestic market. The fourth quarter of 2013 has witnessed steady inflow of donor funding that has boosted confidence and allowed the government to resume spending.

Honduras

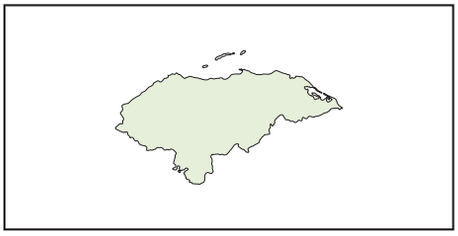

Honduras is a lower-middle income country facing significant challenges, with more than two thirds of the country's population living in poverty. Since the 2008-2009 global economic crises, Honduras has experienced a moderate recovery, propelled by public investments, exports, and higher remittances. The World Bank has worked with the government to design a support program to help Honduras deal with its development challenges, which include the country's vulnerability to external shocks, as the agricultural sector has lost about one-third of its purchasing power in the past two decades, largely due to the decline in prices for export crops, particularly bananas and coffee. Honduras is also susceptible to disasters such as hurricanes and droughts.

पाउण्ड स्टर्लिंग

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जी बी पी पाउण्ड डॉलर के मुक़ाबले बहुत तेजी से चढ़ा तथा लंदन क्लोजिंग दरों के अनुसार 1.5102 से 1.6731 के बीच रहा। इसकी तेजी का प्रमुख कारण रोजगार तथा उत्पादकता में वृद्धि रहा। यू के में आर्थिक गतिविधियों ने ज़ोर पकड़ा तथा मुद्रास्फीति की दर भी 2 प्रतिशत के स्तर पर लौट आई। मांग में तेजी सहित इसके अधिक व्यापक होने, अनिश्चितता में कमी, ऋण की सुलभता तथा प्रोत्साही मौद्रिक नीतियों के सशक्त योगदान से अर्थव्यवस्था के तेजी पर बने रहने की उम्मीद है। बेरोजगारी की दर के भी मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित 7 प्रतिशत की अंतिम सीमा तक पहुँच जाने का अनुमान है। तथापि समिति के विचार से श्रम बाजार में अभी भी अतिरिक्त क्षमता है।

मुद्रास्फीति की दर के अगले 3 से 6 महीने तक लक्ष्य के आसपास ही बने रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति के विचार से इन परिस्थितियों तथा अतिरिक्त क्षमता से बैंक दर बढ़ाने से पहले आने वाली मंदी को अच्छी तरह से वहन करने का स्कोप है। किन्तु अभी भी घरेलू तथा विदेशी माहौल में व्याप्त माहौल से बैंक दरों के कुछ समय तक न्यून स्तर पर ही बने रहने की उम्मीद है। इस रुझान के जारी रहने के साथ-साथ यू के की अर्थव्यवस्था के आगे भी गति पकड़े रहने का अनुमान है। घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार तथा विशेषकर बेरोजगारी में कमी से गति पकड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा समय से पहले ही मौद्रिक नीतियों में कड़ाई लाने पर विचार किया जा सकता है। इन स्थितियों में पाउण्ड के यू एस डॉलर की तुलना में और मजबूत होने का अनुमान है। यथा 31 मार्च 2014 को पाउण्ड 1.6673 यू एस डॉलर पर था।

ब्राज़ीलियाई रियाल

ब्राज़ीलियाई रियाल 18 जनवरी 1999 से ही यू एस डॉलर के मुक़ाबले उतार चढ़ाव के लिए मुक्त रहा है। ब्राज़ीलियाई रियाल अधिकांशतः देश की घरेलू नीतियों पर निर्भर करता है। विश्लेषकों का मानना है की ब्राज़ील जैसे देश उच्च प्रतिफल के चलते निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं और यहाँ निवेशक क्षेत्र में जोखिमों के बावजूद वर्ष भर भारी निवेश करते रहते हैं। मुद्रा के लगातार मजबूत रहने को लेकर को लेकर हस्तक्षेपों की संभावना के चलते ब्राज़ील में चिंता बनी हुई है।

राजकोषीय गिरावट से क्रेडिट रेटिंग के गिर जाने के संभावित खतरे तथा फेडरल रिज़र्व द्वारा प्रोत्साहन पैकेज को वापस लिए जाने के कारण मांग के घाट जाने के अनुमानों के चलते 2013 में ब्राज़ीलियाई रियाल 13 प्रतिशत गिरा। मुद्रा में यह वार्षिक गिरावट 2008 में आए वित्तीय संकट के बाद आई गिरावट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है । सरकार द्वारा बाजार में तरलता बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। नीति निर्माताओं का यह मानना है की मुद्रा में आई यह गिरावट देश की आर्थिक स्थिति का सही प्रतिबिंब नहीं है।

पिछले साल की लगातार गिरावट तथा इस साल में कमजोर शुरुआत के बावजूद ब्राज़ीलियाई मुद्रा स्थिर हुई है तथा इसने यू एस डॉलर की तुलना में अपनी शुरुआती हानि को पूरा कर लिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा नीतियों में ढील देने के संकेतो के अलावा मुद्रास्फीति में कमी, सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन, चौथी तिमाही में जी डी पी में हुई आशा से बेहतर वृद्धि ने मुद्रा को कुछ मजबूती प्रदान की है। इसके बावजूद मुद्रा निवेशकों के जोखिम अनुमानों के अनुसार घट-बढ़सकती है। बाजार के अनुमान के अनुसार मुद्रा और अवमूल्यित हो सकती है। यथा 31 मार्च 2014 को 1 यू एस डॉलर 1.6673 ब्राज़ीलियाई रियल पर था।

भारतीय रुपया

चौथी तिमाही में सकारात्मक परिदृश्य जैसे भुगतान शेष रिपोर्ट, चालू खाते के घाटे में कमी, कम हुई मुद्रा स्फीति तथा आम चुनाव की घोषणा ने भारतीय शेयर बाजार में तेजी लाने के साथ साथ भारतीय रुपये को भी अन्य क्षेत्रीय मुद्राओं की तुलना में मजबूती प्रदान की। बाजार अनुमानों के अनुसार भारतीय रुपया आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है। हालांकि इस सकारात्मक परिदृश्य के बावजूद भारतीय रुपये के एक सीमा के बाद मजबूत होने की आशा कम ही दिखती है। मुद्रा की मजबूती से आयात सस्ता होगा। वस्तुतः चालू खाते के घाटे में कमी का मुख्य कारण स्वर्ण आयात में कमी रहना था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस समय मांग में वृद्धि को रोक पाने की स्थिति में नहीं है।

भारतीय रुपये की मजबूती से निर्यातकों को निराशा होगी क्योंकि इससे उनका मार्जिन कम होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस समय यह जोखिम भी उठाने की स्थिति में नहीं है। विकास दर के भी बहुत शानदार रहने की उम्मीद नहीं है क्योंकि तेल तथा गैर तेल आयातों की मांग में कमी के चलते आयातों में तेजी से कमी आई है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। इन परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की भी काफी कम संभावनाएं हैं। अप्रैल मई में होने वाले आम चुनावों कों देखते हुए राजनैतिक अस्थिरता के भय से लोगों ने अपने निवेश रोक रखे हैं। इसलिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावनाएं अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में ही हैं।

अतः चालू खाते के घाटे में आई कमी, कम मुद्रास्फीति विश्वसनीय नीतिगत माहौल तथा सशक्त पूंजी आवकों के चलते भारतीय मुद्रा में आई इस मजबूती के कुछ और समय तक जारी रहने की उम्मीद है। तथापि आगामी आम चुनाव भारतीय रुपये के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। यथा 31 मार्च 2014 को 1 यू एस डॉलर 60.053 भारतीय रुपये पर था।

भारतीय इलेक्ट्रोनिक उद्योगः चुनौतीपूर्ण परिदृश्य तथा चीन का महत्व

इलेक्ट्रोनिक उद्योग में भारत का प्रवेश बहुत बाद में हुआ जब भारत सरकार द्वारा 1965 के आस पास स्पेस तथा डिफेंस के क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई। उद्योग विशेषकर 1980 के आस-पास अपने उच्च स्तर पर पहुंचा। किन्तु उद्योग नीतिगत प्रोत्साहनों के अभाव में अपने इस प्रदर्शन को आगे के दशकों में बरकरार नहीं रख सका।

आईटी करार पर हस्ताक्षर के साथ ही सीमा शुल्क की समाप्ति तथा सीमा प्रशुल्कों में कमी से इलेक्ट्रोनिक उद्योग पर दबाव बढ़ा। इलेक्ट्रोनिक कँपोनेंट का उत्पादन अन्य क्षेत्रों के समान नहीं बढ़ा सका तथा सुलभ और सस्ते आयातों के चलते एम एस एम ई क्षेत्र बाजार में अपनी पैठ नहीं बना सका। आई टी करार पर हस्ताक्षर से कुछ कँपनियों ने बाज़ार में अपना दबदबा बना लिया। विनिर्माण तथा नवोन्मेषी क्षेत्र में नए उद्यमों का प्रवेश काफी कठिन हो गया।

वर्तमान परिदृश्य

वर्ष 1995-96 से 2012-13 के दौरान भारत में इलेक्ट्रोनिक्स का उत्पादन 14.4 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़ा। संचार तथा प्रसारण उपकरण खंड 19.7 प्रतिशत की सी ए जी आर से सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला खंड रहा; उसके बाद कँप्यूटर हार्डवेयर तथा रणनैतिक उपकरण खंड रहा **(चार्ट)**। इलेक्ट्रोनिक कँपोनेंट खंड की वृद्धि दर सबसे कम रही जो कि एक चिंता का विषय है क्योंकि इस उद्योग में महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन इलेक्ट्रोनिक कँपोनेंट खंड के चलते ही होता है।

इलेक्ट्रोनिक सामानों का भारतीय आयात और निर्यात दोनों ही 2010-11 में शीर्ष पर पहुँचने के बाद 2011-12 तथा 2012-13 में घटा है। निर्यात वृद्धि में जहां सबसे ज्यादा गिरावट आई तथा यह 2011-12 में गत वर्ष के 52.1 प्रतिशत से घटकर 7.4 प्रतिशत हो गई। 2012-13 में तो यह और भी घटकर -7.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। आयातों में गिरावट निर्यात के तुलना में कम रही। भारत इलेक्ट्रोनिक सामानों का निवल निर्यातक है जिसका वर्ष 2012-13 में विश्व के साथ व्यापार घाटा 21.6 बिलियन यू एस डॉलर तथा चीन के साथ व्यापार घाटा 14.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा है। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रोनिक सामानों में चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है तथा यह अंतिम उत्पाद, सब असेंबली व कम्पोनेंट श्रेणी में क्रमशः 57 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत रहा है।

भारत सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक नीति लाकर इस उद्योग की चिंताओं को कम करने का प्रयास किया है। इस नीति में देश की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहित विदेशी बाज़ारों के लिए भी इस उद्योग को विश्वस्तरीय व प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत कई कदम उठाए गए हैं जिनमें एम सिप (ई एस डी एम क्षेत्र में निवेश के लिए सब्सिडी) योजना, इलेक्ट्रोनिक क्लस्टरों की स्थापना, बाजार पहुँच योजना, सेमी कँडक्टर वाटर फैब विकास, इलेक्ट्रोनिक उद्योग विकास निधि, अनिवार्य सुरक्षा मानक, तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास आदि प्रमुख हैं।

चार्ट : भारत में इलेक्ट्रोनिक्स का उत्पाद (रुपए करोड़)

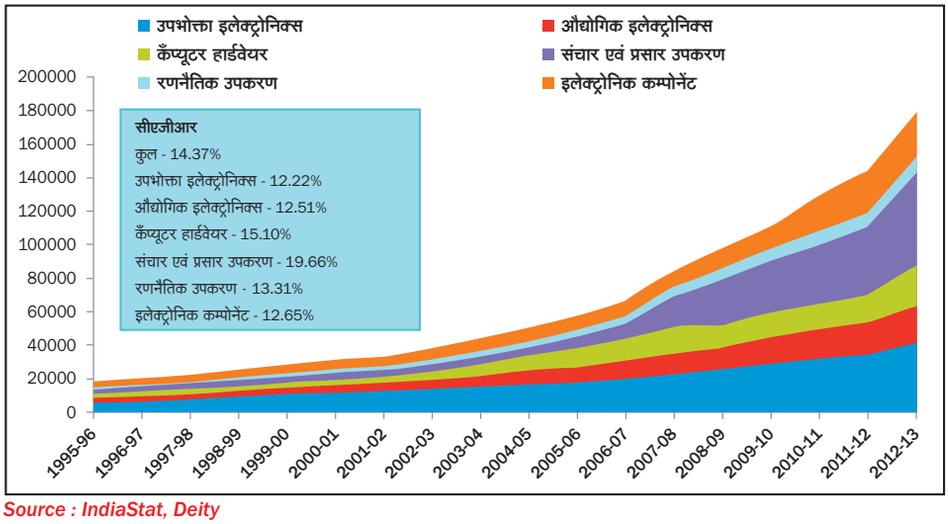

Source : IndiaStat, Deity

भावी रणनीति क्षमता निर्माण में चीन की भूमिका

भारतीय इलेक्ट्रोनिक उद्योग के संदर्भ में शायद यह कहावत कि 'चीन भारत का प्रतिद्वंदी है, चीन एक ग्राहक है और चीन एक अवसर है' बिल्कुल सही है। जहां तक चीन के साथ इलेक्ट्रोनिक उद्योग के व्यापार घाटे का संबंध है चीन भारत का प्रतिद्वंदी है और खतरा भी है। भारत को नई प्रद्योगिकी की सहायता लेकर इलेक्ट्रोनिक उद्योग में उत्पादन सुविधाओं कों उन्नत करने पर विचार करना चाहिए। चीन एक ग्राहक है क्योंकि चीन तेजी से तरक्की करती एक अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत के लिए कई संभावनाएँ हैं। इसमें चिकत्सा उपकरणों की भारी मांग है। चीन द्वारा उच्च खंड में प्रवेश करने के बावजूद भारत इसके निम्न खंड में गुणवत्ता बढ़ाकर इस खंड को अपनी सेवाएँ दे सकता है। चीन एक अवसर है क्योंकि इलेक्ट्रोनिक उद्योग खंड में देश से एफ डी आई बाहर जा रहा है। चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में तैयार इलेक्ट्रोनिक उद्योग खंड को विकसित करने में मदद कर सकता है। चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेंट उद्योग खंड को भी विकसित करने में मदद कर सकता है जहां चीन से जनवरी 2003 दिसंबर 2013 के दौरान केवल 1.2 प्रतिशत एफ डी आई ही प्राप्त हुआ है।

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्त्रोतों / माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रामाणिक हैं । प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है ।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005

दूरभाष : +91-22-2217 2600
फैक्स : +91-22-2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

मार्च 2014
खंड XXVIII अंक I

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ - फीडबैक (प्रतिपुष्टि) फार्म

कृपया इसे और बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें ।

1. आप किससे संबंधित हैं *(जो लागू हो उस पर टिक करें)*
   - ☐ सरकारी संस्था
   - ☐ गैर-सरकारी संस्था
   - ☐ कार्पोरेट
   - ☐ निर्यातक
   - ☐ शैक्षणिक संस्था
   - ☐ व्यक्तिगत
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

2. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आपके विचार
   - ☐ समझने में आसान एवं उपयोगी
   - ☐ थोड़ा सहायक
   - ☐ व्यापक
   - ☐ बिल्कुल उपयोगी नहीं

3. आप किस क्षेत्र में रूचि रखते हैं? *(कृपया टिक करें)*
   - ☐ क्षेत्रीय/औद्योगिक परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें*
   - ☐ देश/क्षेत्रीय परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें*
   - ☐ व्यवसाय अवसर एवं संविदा
   - ☐ एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएँ
   - ☐ तिमाही समाचार
   - ☐ देशों का अवलोकन
   - ☐ मुद्रा की प्रवृत्तियाँ
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

4. क्या आप हमारे प्रकाशन से संतुष्ट हैं?
   - ☐ बेहद संतुष्ट
   - ☐ संतुष्ट
   - ☐ सामान्य
   - ☐ असंतुष्ट

5. क्या हमारा प्रकाशन आपके लिए उपयोगी रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ इसने काफी मदद की
   - ☐ यह उपयोगी रहा
   - ☐ कह नहीं सकते
   - ☐ यह उपयोगी नहीं रहा
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

6. आपको हमारा प्रकाशन कब से मिल रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ एक वर्ष से कम समय से
   - ☐ लगभग 1-3 वर्ष से
   - ☐ लगभग 3-5 वर्ष से
   - ☐ 5 वर्ष से अधिक समय से

7. आप यह प्रकाशन किस भाषा में चाहेंगे?
   - ☐ अंग्रेजी
   - ☐ हिन्दी

8. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
   - ☐ हाँ
   - ☐ नहीं

   यदि हाँ, तो कृपया लिखें!

कृपया अपने सुझाव/फीडबैक हमें फैक्स/ई-मेल/डाक से निम्नलिखित पते पर भेजें : निगमित कार्य समूह, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ परेड, मुंबई - 400 005

फैक्स : +91-22 22182572, ई-मेल : cag@eximbankindia.in

नाम :_____

संपर्क विवरण :_____